साप्ताहिक

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 18-24 मार्च 2024 वर्ष-9, अंक-48

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ:-8, मूल्य:- 2 रुपए

-सरकार ने खरीदी का लक्ष्य 40 फीसदी बढ़ाया, किसानों को बोनस मिलेगा सिर्फ 125 रुपए

समर्थन जैसा मंडी का मूल्य! सौ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य

साल करीब 1130 लाख मीट्रिक टन के करीब गेहूं का उत्पादन होगा

» भारत में इस साल 324 लाख हेक्टेयर के करीब हुई

» समितियां पैसे आते ही काट लेती हैं कर्ज की राशि

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश सरकार को 22 मार्च से शुरू हो रही रबी सीजन की गेहूं खरीदी में 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया है, जो पिछले साल से करीब 40 फीसदी ज्यादा है। वहीं, गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में शामिल पंजाब को 130 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य मिला है। पिछले साल मप्र को 71 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई थी। हालांकि इस खरीदी में सबसे बड़ी परेशानी समर्थन मूल्य है। इस बार मप्र गेहूं पर 125 रुपए बोनस बढ़ने के बाद भी एमएसपी 2400 रुपए प्रति क्विंटल ही पहुंची है। जो मंडियों के बारबर का भाव है। भोपाल मंडी में 2200 से 2600 रुपए तो इंदौर मंडी में 2250 से 2600 रुपए तक औसन मूल्य मिल रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए लक्ष्य प्राप्त करना टेढ़ी साबित होगा। इस बीच खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि चार बार बढ़ाई है। इधर, सरकार द्वारा खुले बाजार में गेहूं की बिकवाली रोकने के बाद एकाएक बाजार में गेहूं के भाव 200-300 रुपए क्विंटल तक उछल गए हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में नए गेहूं का सीजन अपनी पीक पर होगा। नया गेहूं मप्र और महाराष्ट्र में आने लगा है। नए गेहूं में रैक लेने वालों की खरीद से गेहूं का भाव 20/25 रुपए तक उत्पादक मंडियों में बढ़ गया है। गौरतलब है कि गेहूं को बोवनी इस बार देश में 324 लाख हेक्टेयर के करीब हुई है, जो गत वर्ष 307 लाख हेक्टेयर में हुई थी। इस साल करीब 1130 लाख मीट्रिक टन के करीब गेहूं का उत्पादन होगा, जबकि सरकार द्वारा पिछले दिनों के दिए गए उत्पादन अनुमान 1120 लाख मेट्रिक टन के आए हैं।

जोरों पर गेहूं की आवक

मध्य प्रदेश के बैतूलगंज अमरवाड़ा लाइन में गेहूं की आवक जोरों पर चल रही है, लेकिन उसी हिसाब से रैंक वाले भी सक्रिय है, क्योंकि तेलंगना कर्नाटकर्ना एवंतमिलनाडु की गेहूं मांग बनी हुई है। मंडियों से गेह की खरीद किसानी माल की 2370/2380 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में कारोबारी कर रहे हैं। कुछ बैंक पॉइंटों पर 2390/2400 रुपए तक का व्यापार हो रहा है। वहीं मालवा-निमाड़ की मडियों में गेहूं की आवक बढ़ने लगी है।

इनका कहना है

किसानों को मंडी में गेहूं बेचना ही पसंद है। एक बड़ा कारण है कि नकद पैसे मिल जाते हैं। सहकारी समितियों में बेचने पर उनके पुराने कर्ज की राशि काट ली जाती है।

गोपालदास अग्रवाल, प्रदेशाध्यक्ष, सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ समिति

सौ मीट्रिक टन का लक्ष्य हासिल करना बहुत मुश्किल है। मंडियों में 2200 से 2700 का भाव है तो किसान सरकार को गेहूं क्यों बेचेंगे। एफसीआई ने किसानों को कहा कि छत्रा लगाकर गेहूं लेंगे जिससे 25 रुपए प्रति क्विंटल अधिक लागत आएगी।

राहुल धूत, प्रवक्ता, भारतीय किसान संघ मध्य भारत प्रांत

प्रदेश में 2200 से 2600 रुपए प्रति क्विंटल औसत दाम है, जो एमएसपी से बराबर हैं। ऐसे में किसान मंडियों में ही बेच रहे हैं। अप्रैल मध्य से आवक बढ़ने पर अगर दाम गिरे तो ही किसान सरकार के पास पहुंचेंगे।

हरीश ज्ञानचंदानी, अध्यक्ष, भोपाल अनाज मंडी

-उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने की घोषणा

करहिया मंडी को हाईटेक मंडी बनाया जाएगा

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि रीवा की करहिया आदर्श मंडी को हाईटेक बनाया जाएगा। मंडी में किसानों और व्यापारियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने रीवा में करहिया मंडी परिसर में आईडीबीआई बैंक की नवीन शाखा का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि करहिया मंडी में किसानों एवं व्यापारियों के लिए ट्रक व अन्य वाहनों के पार्किंग स्थान, शेड के साथ ही हम्मालों के लिए रेस्ट हाउस भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी जनसुविधा का केन्द्र बन गई है। उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में हितग्राहियों को मुद्रा योजना के चेक प्रदान किए।

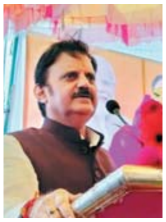

-आर्गेनिक हल्दी होने के कारण कई राज्यों में डिमांड

शहडोल की आर्गेनिक हल्दी को मिलेगा जीआई टैग!

शहडोल।

शहडोल की हल्दी को एक जिला एक उत्पाद के तहत जीआइ टैग देने की तैयारी चल रही है। हल्दी की खेती के लिए यहां की जलवायु बेहतर है, इसलिए जिले में हल्दी का अच्छा उत्पादन होता है। विशेष गुणवत्ता वाली आर्गेनिक हल्दी होने के कारण शहडोल की हल्दी की डिमांड कई राज्यों में है। जिले के आदिवासी किसान रोमा, सेलम, सोनम और सरिहट हल्दी की खेती करते हैं। जिले के गोहपारु, जयसिंहनगर एवं बुढ़ार के करीब 35000 से ज्यादा किसान हल्दी की खेती करते हैं प्रत्येक किसान दो से पांच क्विंटल हल्दी का उत्पादन करता है। हल्दी को जीआई टैग मिलने के बाद किसानों को मार्केटिंग में मदद मिलेगी और खरीदारों को भी अच्छा सामान मिल सकेगा। हल्दी का उपयोग भोजन में तो होता ही है। आयुर्वेद में इसे एंटीबायोटिक माना गया है। जिले के गोहपारु, जयसिंहनगर एवं बुढ़ार के किसान पांच साल से हल्दी की खेती कर रहे हैं।

हल्दी की खेती की शुरुआत भी गोहपारू के गांव सरिहट से हुई

गोहपारू विकासखंड का गांव सरिहट ऐसा है, जहां के सभी किसान इस समय हल्दी की खेती कर रहे हैं। हल्दी की खेती की शुरुआत भी यहीं से हुई, इसलिए सरिहट की हल्दी के नाम से यहां से उत्पादित हल्दी को जाना जा रहा है। एक जिला एक उत्पाद में हल्दी को शामिल करने के बाद खेती का रकबा और उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। 1120 हेक्टेयर में हल्दी की खेती हो रही है और बीस हजार मीट्रिक टन उत्पादन भी हो रहा है। छोटे-छोटे रकबे में जिले के 3500 से ज्यादा किसान हल्दी की खेती कर रहे हैं। जिला प्रशासन के साथ प्रयास करते हुए उद्यानिकी विभाग ने तीन प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहा है।

एक यूनिट जल्द चालू हो जाएगी

एक यूनिट के लिए मशीनें आ गई हैं और इसी माह यह यूनिट चालू हो जाएगी। इसके साथ दो और यूनिटों का भी निर्माण कार्य जारी है। यूनिट चालू होने के बाद हल्दी की गुणवत्ता बढ़ेगी और किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। अभी किसान 150 से 200 रुपये प्रति किलो की दर से हल्दी का विक्रय कर रहे हैं। प्रोसेसिंग यूनिटें चालू होने के बाद किसानों को हल्दी की कीमत 200 से 250 रुपए प्रति किलो मिलना संभव होगा। अभी हल्दी उत्पादन में शहडोल जिला प्रदेश में छठवें स्थान पर है,लेकिन इसी गति किसान हल्दी की खेती में रुचि लते रहे तो बहुत जल्दी नंबर एक पर भी पहुंच सकता है।

किसान ने आम खेती करके अपनी तकदीर बदल दी, दूसरों के लिए बना रोल मॉडल

आम की खेती ने बना दिया किसान को खास सिर्फ ऑनलाइन बिक्री से कमाए पांच लाख

बड़ी मंडी होने के कारण लोगों को आम बेचने के लिए शहर से बाहर नहीं जाना होता

भोपाल। जागत गांव हमार

आम का सीजन शुरू हो गया है। कुछ क्षेत्रों में आम आना शुरू हो गया है तो कुछ में अभी मंजर लग रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश से आम की अनोखी खेती करने वाले एक किसान के सफलता की कहानी आई है, जिसने एक ही सीजन में 5 लाख रुपए के आम ऑनलाइन ही बेच डाले। ऑफलाइन का बिजनेस अलग है। इस किसान के बगीचे में आम के दो हजार पेड़ हैं। इस किसान ने आम खेती करके अपनी तकदीर बदल दी है। अलीराजपुर जिले के किसान युवराज सिंह के बागीचे में लंगड़ा, केसर, चौसा, सिंदूरी, राजापुरी, हापुस जैसे 26 वैरायटी के आम के पेड़ लगे हैं। इसलिए उनका बगीचा अन्य, लोगों से अलग है और यही उनकी आय बढ़ने का राज भी है। सिंह कहते हैं कि इतनी किस्मों के आम के बावजूद सबसे खास नूरजहां है। वो जिले के कट्ठीवाड़ा से नूरजहां आम का पौधा ग्राफ्टिंग करके लाए थे। उसे अपने बागीचे में लगाया और एक छोटा सा पौधा आज आम के पेड़ के रूप में बनकर तैयार हो गया है। इसकी खासियत है कि एक आम का वजन लगभग तीन किलो होता है, जिसकी कीमत प्रति किलो एक हजार रुपए होती है।

बागवानी से आय बढ़ाने की कोशिश- प्रदेश में खेती को लाभदायक बनाने के लिए राज्य सरकार कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए बागवानी फसलों की मदद ली जा रही है। कई किसानों ने अपनी मेहनत से इस क्षेत्र में अच्छी कामयाबी भी हासिल की है। इसमें अलीराजपुर के किसान युवराज सिंह भी शामिल हैं। जिले के ग्राम छोटा उंडवा के किसान युवराज ने अपने पुश्तैनी बागीचे को विस्तार देते हुए आम का बागीचा तैयार किया है। उन्हें आम के स्वाद से विशेष पहचान मिली है, क्योंकि उनके बाग में कई किस्मों के आम के पेड़ हैं।

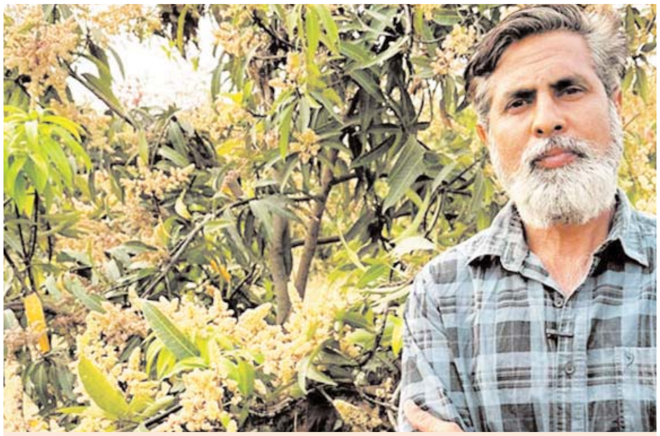

एडवांस मिलती है पेमेंट

युवराज सिंह कहते हैं कि अलीराजपुर जिले की मिट्टी में नमी होने से यह आम की खेती के लिए उपयुक्त है। यहां पैदा होने वाले आम का स्वाद पूरे देश में विशेष पहचान रखता है। वो वर्ष अलग-अलग वैरायटी के आम की सीधी बिक्री अपने खेत से करते हैं। अलीराजपुर के आमों की खासियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सीजन के पहले ही लोग आम की बुकिंग कर एडवांस पेमेंट कर देते हैं।

बाग में 2000 से अधिक पेड़

युवराज कहते हैं कि उन्होंने अपने दादा और पिताजी को हमेशा से आम के बागीचे पर काम करते देखा है। उन्हीं से प्रेरणा लेकर सात साल पहले 500 आम के पौधे बागीचे में लगाए। अब इसमें केसर व अन्य आम की वैरायटी के कुल 2 हजार से अधिक पेड़ हो गए हैं। देश के विभिन्न शहरों में होने वाले आम महोत्सव में उन्हें पिछले एक दशक में कई बार प्रथम पुरस्कार मिला है।

ऑनलाइन बिक्री को बनाया मंच

सिंह ने बताया कि बीते वर्ष उन्होंने ऑनलाइन बाजार के माध्यम से 5 लाख रुपए का आम एक सीजन में बेचा है। इसके अलावा 5-5 किलों के बॉक्स तैयार करके ऑनलाइन और मंडी में दोनों तरह से आम बेचा है। अलीराजपुर जनजातीय क्षेत्र होने के कारण यहां के लोगों का आम ही मुख्य आय का साधन है। बड़ी मंडी होने के कारण लोगों को आम बेचने के लिए शहर से बाहर नहीं जाना होता है।

आम उत्पादन में टॉप पांच राज्य

इधर, आम का उपयोग लोग कई तरीके से करते हैं। लोग इसका सेवन फल, जूस या सेक के रुप में करते हैं। साथ ही इसकी चटनी और अचार का भी सेवन किया जाता है। वहीं यह स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभकारी होता है। भारत में सबसे अधिक आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। यहां की मिट्टी और जलवायु आम के उत्पादन के लिए अनुकूल है। यहां के किसान हर साल बंपर आम का उत्पादन करते हैं। देश की कुल आम उत्पादन में यूपी का 20.85 फीसदी हिस्सेदारी है। आम की खेती भारत में अग्रणी व्यावसायिक खेती में से एक है। यह अपनी खुशबू और मीठे स्वाद के लिए काफी मशहूर है। वहीं उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। देश के कुल आम उत्पादन में इस राज्य की हिस्सेदारी 20.04 फीसदी है। यह सिर्फ अपने स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। इसमें कई तरह के विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं उत्पादन के मामले में भारत के टॉप तीन राज्यों में तीसरा नंबर बिहार का है। यहां आम की 11.19 फीसदी पैदावार होती है। वहीं आम खाने के शौकीन लोग गर्मी का दिन आते ही लोग आम को खूब चाव से खाते हैं। अब जान लीजिए कि आम उत्पादन में चौथे स्थान पर कर्नाटक है। इस राज्य के में 8.06 फीसदी आम का उत्पादन करते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (2022-23) के आंकड़ों के अनुसार आम के पैदावार में पांचवें स्थान पर तमिलनाडु है। यहां के किसान हर साल 5.65 फीसदी आम का उत्पादन करते हैं। वहीं ये पांच राज्य मिलकर 65 फीसदी पैदावार करते हैं।

सीएम ने मप्र राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 25वीं बैठक में कहा

वन्य जीवों के प्रति जागरूकता लाने चलाना होगा अभियान, होमगार्ड जवानों को देंगे प्रशिक्षण

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जनसामान्य को वन्य जीवों के आचार-व्यवहार से परिचित कराने तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रावधानों के बारे में जागरूकता पर केन्द्रित अभियान चलाना आवश्यक है। घड़ियाल अभयारण्य के संबंध में जनसामान्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए भी गतिविधियां संचालित की जाएं। निजी इकाइयों तथा व्यक्तिगत स्तर पर जनसामान्य द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में व्यवस्था विकसित करने पर भी विचार-विमर्श होना चाहिए। सर्पदंश से लोगों को बचाने के लिए प्रत्येक थाना स्तर पर सांप पकड़ने वालों के संबंध में जानकारी हो तथा पकड़े गए सांपों का संरक्षण भी व्यवस्थित तरीके से किया जाए।

होमगार्ड के जवानों को सांप पकड़ने का प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चीता पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत चीतों की संख्या बढ़ने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 25वीं बैठक को मंत्रालय में संबोधित कर रहे थे।

अनुमतियों पर विचार-विमर्श

बैठक में नरसिंहगढ़ अभयारण्य, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा-मेलघाट टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, बगदरा अभयारण्य, संजय टाइगर रिजर्व, सोन घड़िया अभयारण्य, कान्हा टाइगर रिजर्व, गांधी सागर अभयारण्य के क्षेत्रों में होने वाले विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए वन्य प्राणी संबंधित अनुमतियों पर विचार-विमर्श हुआ।

गिद्धों की संख्या में वृद्धि

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में गिद्धों की संख्या में वृद्धि हुई। इस वर्ष के प्रारंभिक ग्रीष्म कालीन आंकलन अनुसार गिद्धों की संख्या 10 हजार 845 हो गई है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के चीता पुनर्वास प्रोजेक्ट में चीतों कुल संख्या 26 हो गई है, जिनमें 13 व्यस्क तथा 13 शावक हैं। गांधी सागर अभयारण्य चीता पुनर्स्थापन के लिए तैयार है और सतपुड़ा से 50 गौर बांधवगढ़ ले जाने की योजना है।

आधुनिक तकनीकी से उद्यानिकी का समग्र विकास पर मंत्री बोले

समृद्ध मप्र के लक्ष्य पूर्ति में उद्यानिकी महत्वपूर्ण घटक

भोपाल। उद्यानिकी एवं सामाजिक न्याय दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि समृद्ध मध्य प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने में उद्यानिकी एक महत्वपूर्ण घटक है। नवीन तकनीकी का उपयोग करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने यह बात उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आयोजित आधुनिक तकनीकी से उद्यानिकी का समग्र विकास विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर कहीं। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कि विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि किसान को समृद्ध ओर खुशहाल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि किसान भाई कृषि के साथ उद्यानिकी गतिविधियों से जुड़कर अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। ऐसे किसान जिनके पास एक या दो एकड़ भूमि है वह परंपरागत फसलों के स्थान पर उद्यानिकी और फ्लोरीकल्चर जुड़कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। मंत्री ने कहा मध्य प्रदेश सरकार के उद्यानिकी विभाग का दायित्व है कि वह किसानों को नवीन तकनीकियों और नवीन शोध के विषय में विस्तार से बतलाएं।

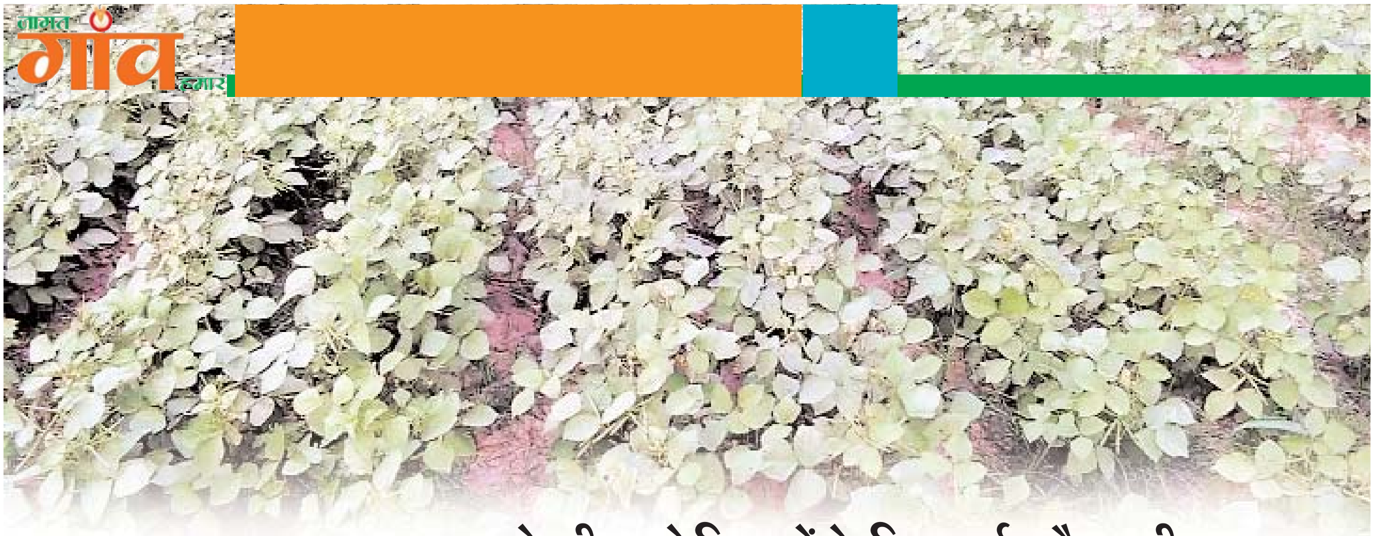

कम लागत, ज्यादा मुनाफा: बोवनी करने किसानों के लिए मार्च-अप्रैल सही समय

बढ़िया उत्पादन के लिए बीज उपचार के बाद ही करें मूंग की खेती

भोपाल। जागत गांव हमार

मूंग की फसल के लिए ज्यादा बारिश नुकसानदायक होती है, ऐसे क्षेत्र जहां पर 60-75 सेमी तक बारिश होती है, मूंग की खेती वहां के लिए सही होती है। मूंग की फसल के लिए गर्म जलवायु की जरूरत पड़ती है। मूंग की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में सफलतापूर्वक की जाती है, लेकिन मध्यम दोमट, मटियार भूमि समुचित जल निकास वाली, जिसका पीएच मान 7-8 हो इसके लिए उत्तम होती है। खेत की पहली जुताई हैरो या मिट्टी पलटने वाले रिजर हल से करनी चाहिए। इसके बाद दो-तीन जुताई कल्टीवेटर से करके खेत को अच्छी तरह भुरभरा बना लेना चहिए। आखिरी जुताई में लेवलर लगाना जरूरी है, इससे खेत में नमी लम्बे समय तक संरक्षित रहती है। दीमक से ग्रसित भूमि को फसल की सुरक्षा के लिए क्यूनालफास 1.5 प्रतिशत चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अंतिम जुताई से पहले खेत में बिखेर दें और उसके बाद जुताई कर उसे मिट्टी में मिला दें।

बीज की मात्रा और बीजोपचार

खरीफ मौसम में मूंग का बीज 12-15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। जायद में बीज की मात्रा 20-25 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना चाहिए। तीन ग्राम थायरम फफूंदनाशक दवा से प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करने से बीज और भूमि जन्य बीमारियों से फसल की सुरक्षित रहती है। 600 ग्राम राइज़ोबियम कल्चर को एक लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ के साथ गर्म कर ठंडा होने पर बीज को उपचारित कर छाया में सुखा लेना चाहिए और बोवनी कर देनी चाहिए। ऐसा करने से नत्रजन स्थरीकरण अच्छा होता है।

इन किस्मों की करें बोवनी

पूसा बैसाखी- फसल अवधि 60-70 दिन, पौधे अर्ध फैले वाले, फलियां लम्बी , उपज 8-10 क्विंटल/ हेक्टेयर

मोहिनी - फसल अवधि 70-75 दिन, उपज 10-12 क्विंटल/ हेक्टेयर पीला मोजैक वायरस व सरकोस्पोरा लीफ स्पॉट रोग के प्रति सहनशील।

पंत मूंग 1 - फसल अवधि 75 दिन (खरीफ) तथा 65 (जायद) दिन , उपज क्षमता 10-12 क्विंटल/ हैक्टेयर।

एमएल 1 - फसल अवधि 90 दिन , बीज छोटा व हरे रंग का, उपज क्षमता 8-12 क्विंटल/हैक्टेयर।

वर्षा - यह अगेती किस्म है, उपज क्षमता 10 क्विंटल/ हैक्टेयर

सुनैना - फसल अवधि 60 दिन, उपज क्षमता 12-15 क्विंटल/ हेक्टेयर ग्रीष्म मौसम के लिए उपयुक्त।

जवाहर 45 - इस किस्म को हाइब्रिड 45 भी कहा जाता है, फसल 75-85 दिन अवधि उपज क्षमता 10-13 क्विंटल/ हेक्टेयर, खरीफ के मौसम के लिए उपयुक्त।

कृष्ण 11- अगेती किस्म फसल अवधि 65-70 दिन , उपज क्षमता 10-12 क्विंटल/ हेक्टेयर।

पन्त मूंग 3- फसल अवधि 60-70 दिन, ग्रीष्म ऋतु में खेती के लिए उपयुक्त, पीला मोजैक वायरस तथा पाउडरी मिल्ड्यू रोधक।

अमृत - फसल आधी 90 दिन यह खरीफ मौसम के लिए उपयुक्त की है, पीला मोजैक वायरस रोग के प्रति सहनशील , उपज क्षमता 10-12 क्विंटल/ हेक्टेयर।

गहाई का समय| मूंग की फलियां जब काली पड़ने लगे सुख जाए तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए अधिक सूखने पर फलियों के चिटकने का डर रहता है। फलियों से बीज को थ्रेसर या डंडे द्वारा अलग कर लिए जाता है।

उत्पादन| वैज्ञानिक विधि से खेती करने पर मूंग की 7-8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल से उपज प्राप्त हो जाती है। सिंचित फसल की औसत उपज 10-12 क्विंटल/ हेक्टेयर तक हो सकती है।

भंडारण| बीज के भंडारण से पहले उसे अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। बीज में 8 से 10 प्रतिशत से अधिक नमी नहीं रहनी चाहिए। मूंग के भंडारण में स्टोरेज बिन का प्रयोग करना चाहिए।

फसल बोवनी का समय

» बोवनी खरीफ और जायद दोनों फसलों में अलग अलग समय पर की जाती है।

» खरीफ में जून के अन्तिम सप्ताह से जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बोवनी करनी चाहिए। जायद में मार्च के प्रथम सप्ताह से अप्रैल के द्वितीय सप्ताह तक बोवनी करनी चाहिए।

» कतार से कतार के बीच दूरी 45 सेमी तथा पौधों से पौधों की दूरी 10 सेमी उचित है। खाद के प्रयोग से पहले मिट्टी की जांच कर लेनी चाहिए।

» मूंग के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 40 किलोग्राम फास्फोरस 20 किलोग्राम पोटाश 25 किलो ग्राम गंधक और 5 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है।

सिंचाई

खरीफ की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फूल आने की अवस्था पर सूखे की स्थिति में सिंचाई करने से उपज में काफी बढ़ोतरी होती है। खरीफ की फसल में वर्षा कम होने पर फलियां बनते समय एक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और जायद की फसल में पहली सिंचाई बुवाई के 30 से 35 दिन बाद और बाद में हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए, जिससे अच्छी पैदावार मिल सकती है।

खरपतवार नियंत्रण

प्रथम निराई बोवनी के 20-25 दिन के भीतर व दूसरी 40-45 दिन में करना चाहिए। फसल की बोवनी के एक या दो दिन बाद तक पेन्डीमेथलीनकी बाजार में उपलब्ध 3.30 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। फसल जब 25 -30 दिन की हो जाए तो एक गुड़ाई कस्सी से कर देनी चहिये या इमेंजीथाइपर की 750 मिली मात्रा प्रति हेक्टयर की दर से पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए।

रोग और कीट नियंत्रण

दीमक - बोवनी से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में क्यूनालफास 1.5 प्रतिशत या क्लोरोपाइरिफास पाउडर की 20-25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला देनी चाहिए।

कातरा - इस कीट की लट पौधों को आरंभिक अवस्था में काटकर बहुत नुकसान पहुंचती है। कतरे की लटों पर क्यूनालफास 1.5 प्रतिशत पाउडर की 20-25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव कर देना चाहिए।

मोयला, सफेद मक्खी और हरा तेला- इनकी रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास 36 डब्ल्यू एसी या मिथाइल डिमेटिन 25 ईसी 1.25 लीटर को प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए।

फली छेदक- फली छेदक को नियंत्रित करने के लिए मोनोक्रोटोफास आधा लीटर या मैलाथियोन या क्युनालफांस 1.5 प्रतिशत पॉउडर की 20-25 किलो हेक्टयर की दर से छिड़काव/भुरकाव करनी चहिए।

रस चूसक कीट- इन कीट की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 200 एस एल का 500 मिली मात्रा का प्रति हेक्टयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। आवश्कता होने पर दूसरा छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें।

चीती जीवाणु रोग - इस रोग की रोकथाम के लिए एग्रीमाइसीन 200 ग्राम या स्टेप्टोसाईक्लीन 50 ग्राम को 500 लीटर में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए।

पीत शिरा मोजैक - यह रोग एक मक्खी के कारण फैलता है। इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल डेमेटान 0.25 प्रतिशत व मैलाथियोन 0.1प्रतिशत मात्रा को मिलकर प्रति हेक्टयर की दर से 10 दिनों के अंतराल पर घोल बनाकर छिड़काव करना काफी प्रभावी होता है।

तना झुलसा रोग - इस रोग की रोकथाम के लिए 2 ग्राम मैकोजेब से प्रति किलो बीज दर से उपचारित करके बोवनी करनी चहिए। बोवनी के 30-35 दिन बाद 2 किलो मैकोजेब प्रति हेक्टयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चहिए।

पीलिया रोग - इस रोग के कारण फसल की पत्तियों में पीलापन दिखाई देता है। इस रोग के नियंत्रण हेतू गंधक का तेजाब या 0.5 प्रतिशत फैरस सल्फेट का छिड़काव करना चहिए।

धब्बा और विषाणु रोग - इन रोगों की रोकथाम के लिए कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम , स्ट्राप्टोसाइलिन की 0.1 ग्राम और मिथाइल डेमेटन 25 ईसी की एक मिली मात्रा को प्रति लीटर पानी में एक साथ मिलाकर पर्णीय छिड़काव करना चहिए।

नमो ड्रोन योजना से गांव की महिलाएं कृषि अर्थव्यवस्था बदल रहीं

एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2029 के लिए नहीं बल्कि मैं 2047 के लिए लगा हुआ हूं। पीएम मोदी ने कहा आज भारत में सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व की शुरुआत हुई है। आज जहां पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी है, उसमें एक भाव निश्चित है कि भारत तेज गति से विकास करता रहेगा। आज मूड ऑफ द नेशन भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, वह भारत को विकसित इकॉनमी की बात कर रहा है।

पीएम मोदी ने अपनी सरकार की तरफ से लिए गए फैसलों और उनसे जनता को होने वाले फायदों के बारे में बताया।

देश की स्टार्टअप क्रांति का जिक्र: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं हेडलाइन नहीं बल्कि डेडलाइन पर काम करने वाला व्यक्ति हूं। इसलिए मैं आज वो बातें भी बताऊंगा जिनको मीडिया कम आकर्षक मानता है। ये वो बाते हैं जिन्हें मीडिया छूना भी पसंद नहीं करता। उन्होंने कहा कि इसमें से ही एक है स्टार्टअप का मसला। आज से 10 साल पहले तक कुछ गिने-चुने स्टार्टअप्स ही भारत में थे। लेकिन आज करीब सवा लाख स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। भारत की स्टार्टअप्स क्रांति की पहचान है कि ये स्टार्टअप्स देश के 600 जिलों में हैं यानी 90 फीसदी हिस्से को कवर कर रहे हैं।

मुद्रा योजना से स्वावलंबी बने युवा : उन्होंने बताया कि टीयर 2 और 3 के शहर स्टार्टअप्स की शुरुआत कर रहे हैं। छोटे शहरों के युवाओं की सफलता ने भारत की स्टार्टअप्स क्रांति को नई पहचान दी है। जिस दल ने कभी स्टार्टअप्स की चर्चा नहीं की, वह भी इसकी बात कर रहा है। हमारे देश में बैंकों से मदद पाने के लिए युवाओं को जगह-जगह गारंटी देनी पड़ती थी। लेकिन मुद्रा योजना ने उन युवाओं को भी लोन की गारंटी दी जिनके पास कुछ नहीं था। बिना गारंटी 26 लाख करोड़ का बैंक लोन छोटे-छोटे उद्यमियों को मिला है। इनमें से करीब आठ करोड़ मुद्रा लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली बार अपना बिजनेस शुरू किया है।

पीएम स्वनिधि वह योजना है जिससे स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ता लोन मिला है और वह भी बिना गारंटी। मैंने गरीबों की अमीरी भी देखी है और अमीरों की गरीबी भी देखी है। इसलिए मैंने स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी लोन देने की हिम्मत दिखाई। दो दिन पहले एक सम्मेलन में देश के कोने-कोने से रेहड़ी पटरी वाले लोग आए थे। लेकिन मीडिया ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जरा कोविड का वह दौर याद कीजिए जब इनके बिना जीवन मुश्किल हो गया था। जिन रेहड़ी पटरी वालों को अनपढ़ कहकर नजरअंदाज किया, आज वो भारत की डिजिटल क्रांति की पहचान बन गए हैं।

ड्रोन उड़ा रही हैं महिलाएं : नमो ड्रोन दीदी वह योजना है जो गांव की महिलाओं को सशक्त बनाती है। पीएम मोदी ने

कहा कि जिन महिलाओं को लोग ट्रैक्टर चलाते देखकर हैरान होते थे, आज वही महिलाएं ड्रोन उड़ा रही हैं। आज बेटियां ड्रोन पायलट हैं। गांव की जिन महिलाओं ने कभी साइकिल तक नहीं चलाई होगी, वो अब ड्रोन पायलट बन रही हैं। इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट सोसायटी में कितना होगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।

बदल रहा है हेल्थ सेक्टर : भारत के हेल्थ सेक्टर में जो बदलाव आ रहा है, उसकी चर्चा भी नहीं होती है। पांच लाख रुपये वाली आयुष्मान योजना के अलावा गांवों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी चल रही है। गांव के लोगों को कोई परेशानी न हो इसके लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए। ये काम लगातार चल रहा है। लेकिन यह काम कभी हेडलाइन नहीं बनता है। इन आरोग्य मंदिरों में सामान्य टेस्टों के अलावा डायबिटीज से लेकर कैंसर तक की जांच होती है। इन मंदिरों को हमने डिजिटली जोड़ा है। देश के गांवों में हो रही इस क्रांति की चर्चा भी बहुत जरूरी है।

मछली का उत्पादन दोगुना: मछली का उत्पादन दोगुना हो गया है, निर्यात भी बढ़ा है। पहली बार पशुपालकों और किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिला। अनाज के भंडारण के लिए सबसे बड़ी योजना चलाई। मुद्रा लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने जिंदगी में पहली बार अपना कोई बिजनेस शुरू किया है। पीएम मोदी ने बताया कि आजादी के बाद पहली बार देश में लाखों नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा अभियान चला। उन्होंने बताया कि सरकार ने कॉपरेटिव मिनिस्ट्री अलग बनाई। इसके बनने के बाद 60 हजार पैक्स के कंप्यूटरीकरण का काम पूरा हुआ। इसी मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू की। पीएम मोदी ने कहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले की सरकारों के समय आपने Ease of Living जैसे शब्द नहीं सुने होंगे। पहले की सरकारों की सोच ही ऐसी नहीं थी, तो वो देश के नागरिकों की Ease of Living पर कैसे ध्यान देती पहले की सरकारों के समय जो पावरफुल थे, वो सुविधाओं के पहले हकदार बन गए थे। साम, दाम, दंड, भेद, सिफारिश और रिश्वत कुछ भी करके वो सुविधाएं हासिल करते थे और बीच में पिसता था देश का सामान्य नागरिक।

गरीबों के 30 हजार करोड़ बचे: पीएम मोदी ने बताया कि एक स्टडी के अनुसार, स्वच्छ भारत अभियान हर साल गरीबों के 60 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा बचा रहा है। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना की वजह से गरीबों के एक लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। हमारी सरकार जनऔषधि केंद्रों पर 80 प्रतिशत डिस्काउंट पर दवाइयां देती है। इस वजह से गरीबों के 30 हजार करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं।

लम्पी स्किनः गांठदार त्वचा रोग-निवारण एवं उपचार

» डा. सौरभ शर्मा
» डॉ. रूचि सिंह
» डॉ. हरी आर
» डॉ. रश्मि विश्वकर्मा
» डॉ.प्रतीक्षा ठाकुर
पशु चिकित्सा विज्ञान विवि. जबलपुर

लम्पी स्किन रोग वायरस गाय और भैंसों को संक्रमित करता है। यह बीमार जानवरों के लिम्फ नोड को प्रभावित करता है, जिससे वे बड़े हो जाते हैं और उनके सिर, गर्दन, पैर, ऊदर, जननांग, और पैरीना पर 2-5 सेंटीमीटर के व्यास के गांठों (कटनी गांठ) के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें उच्च तापमान, दूध की आपूर्ति में तेज गिरावट, आँखों और नाक से निकलने वाला तरल, लार टपकाना, भूख की कमी, अवसाद, क्षतिग्रस्त त्वचा, और कुष्ठ होते हैं, जो और चेतावनी संकेत और लक्षण हैं। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, संक्रमण और लक्षण के बीच का समय, या अंडन काल, लगभग 28 दिन है। संक्रमित जानवर मुख या नाक से सीधे वायरस के निकास और पानी की ट्रफो के साथ वायरस को स्थानांतरित कर सकते हैं।

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और एफएओ दोनों चेतावनी देते हैं कि बीमारियों का प्रसार गंभीर आर्थिक हानि की ओर ले जा सकता है। यह बीमारी गाय की दूध उत्पाद को कम करती है क्योंकि मुंह के छाले जानवर को कमजोर बना देते हैं और उनकी भूख को खो देते हैं। एलएसडी के लिए कई नैदानिक उपलब्ध हैं। लम्पी स्किन स्थिति को रोकने और नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छे तरीके में टीकाकरण और आंध्र प्रतिबंध शामिल हैं। इस बीमारी के लिए एक विशिष्ट इलाज उपलब्ध नहीं है, इस बीमारी के लिए केवल गाय के लिए सहारा है। इस अध्ययन का प्रमुख लक्ष्य लक्षणों, सबसे सटीक निदान के तरीके, उपचार, और संयंत्रण की नियंत्रण के लिए डेटा जमा करना है ताकि संक्रमण का प्रसार रुक सके और एलएसडीवी प्रबंधन के लिए भविष्य की संभावनाएं अन्वेषित की जा सके।

जनसांख्यिकी: यह पहली बार 1929 में जाम्बिया में रिपोर्ट किया गया था और पूरे अफ्रीकी देशों में मवेशी समुदाय में तेजी से फैल गया। लम्पी स्किन डिजीज का पहला मामला भारत में वर्ष 2019 में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्यों में दर्ज किया गया था। राजस्थान सबसे अधिक प्रभावित राज्य रहा, जहां लगभग 13 लाख पशु संक्रमित हुए। पंजाब में लगभग 6 लाख पशु प्रभावित हुए। गुजरात में करीब 2 लाख पशुओं में संक्रमण फैला। उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में भी हजारों पशु प्रभावित हुए। गांठदार त्वचा रोग भारत में एक नवीन और गैर-जूनोटिक रोग के रूप में उभरा है, हाल ही में अगस्त 2022 में गुजरात में इसका बड़ा प्रकोप हुआ, जो बाद में 15 अन्य राज्यों में फैल गया, जिससे लगभग 2 मिलियन मवेशी संक्रमित हो गए। मध्य प्रदेश में गांठदार त्वचा रोग पहली बार अगस्त 2020 में अनूपपुर जिले में रिपोर्ट किया गया। वर्तमान प्रकोप का राज्य पर भारी प्रभाव पड़ा है, जिससे अगस्त और दिसंबर 2022 के बीच 3,878 गांवों में 26,888 जानवर संक्रमित हो गए हैं।

लक्षण: बीमारी के निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं।

उच्च तापमान: संक्रमित जानवरों में तापमान की वृद्धि होती है, जो उनकी स्वास्थ्य स्थिति को प्रभावित कर सकती है।

गांठें और गांठों का उत्पन्न होना: जानवरों की त्वचा पर 2-5 सेंटीमीटर के व्यास की गांठें बन सकती हैं, जो उनके सिर, गले, पैर, ऊदर, जननांग, और पैरीना पर पाई जा सकती हैं।

दूध की कमी: संक्रमित गायों में दूध की आपूर्ति में कमी हो सकती है, जिससे उद्योगिक दृष्टि से भी नुकसान हो सकता है।

तरल स्राव से संबंधित लक्षण: आंखों और नाक से तरल निकलना, लार टपकाना, और थूकना भी संकेत हो सकते हैं।

अन्य लक्षण: उच्चतम तापमान, त्वचा की क्षति, भूख की कमी, अवसाद, और कुष्ठ जैसे अन्य लक्षण भी दिख सकते हैं।

लम्पी स्किन बीमारी के कारण: लम्पी स्किन बीमारी का कारण एक वायरस है, जिसे लम्पी स्किन डिजीज वायरस कहा जाता है। यह वायरस पशुओं को संक्रमित करके उन्हें लम्पी स्किन बीमारी में प्रभावित करता है। निम्नलिखित कारण लम्पी स्किन बीमारी के फैलने के प्रमुख कारण हो सकते हैं-

संश्लेषण: संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु के संपर्क में आने से वायरस का प्रसार हो सकता है।

संवहन: कुछ प्रजातियों के कीट (जैसे कि मच्छर और तटबंधु मक्खी) लम्पी स्किन बीमारी के वायरस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकती हैं, जिससे बीमारी फैलती है।

मुंह या नाक से सीधा प्रसार: संक्रमित पशु मुंह या नाक से वायरस सीधे अन्य पशुओं को पहुंचा सकते हैं।

संयुक्त खाद्य और पानी का सेवन: संक्रमित और स्वस्थ पशुओं को संयुक्त खाद्य और पानी की जगहों से वायरस का प्रसार हो सकता है। कृत्रिम इंजेक्शन के द्वारा भी वायरस का प्रसार हो सकता है।

इन कारणों के संयुक्त प्रभाव से लम्पी स्किन बीमारी का प्रसार होता है, जो पशुओं की सेहत को प्रभावित करके उत्पादकों और किसानों को आर्थिक हानि पहुंचा सकती है।

पहचान के तरीके: ऊपर बताए गए लक्षणों के आधार पर पूर्व जाँच की जा सकती है। पशु चिकित्सक गांठों की जांच करेंगे और अन्य लक्षणों का निरीक्षण करेंगे। लंपी स्किन डिजीज केवल मवेशियों को संक्रमित करती है, इंसानों पर असर नहीं। कुछ मामलों में, रक्त परीक्षण या अन्य नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है, हालांकि अभी तक इनकी सटीकता पूरी तरह से स्थापित नहीं है। अगर आपको अपने पशुओं में इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें. जल्दी पहचान और इलाज से पशुओं को इस बीमारी से बचाने में मदद मिल सकती है।

लम्पी स्किन बीमारी के कारण आर्थिक हानि: लम्पी स्किन बीमारी गाय और भैंसों में होने वाली एक गंभीर बीमारी है जो कृषि उद्योग में आर्थिक हानि का कारण बन सकती है। इस बीमारी के कारण खाद्य उत्पादन में कमी, पशुओं के संख्या में गिरावट, और उत्पादकों को नुकसान हो सकता है।

पशुओं की मृत्यु और गिरावट: संक्रमित पशुओं की मृत्यु होने से पशुओं की संख्या में कमी हो सकती है, जिससे उत्पादकों को नुकसान होता है।

निवारण और नियंत्रण: टीकाकरण: एलएसडी से बचाव के लिए हाल ही में भारत ने लम्पी-प्रोवैकइंड नाम की एक स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है। पशुपालकों को अपने मवेशियों का इस वैक्सीन से टीकाकरण करवाना चाहिए।

आइसोलेशन और कीट नियंत्रण: संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। खून चूसने वाले कीड़ों से बचाएं।

जागरूकता और स्वच्छता: पशुपालकों को अपने पशुओं के स्वास्थ्य पर नजर रखनी चाहिए और किसी भी असामान्य लक्षण को देखने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए।

पालक साग के औषधीय गुण

डा. पल्लवी सिंह
पीएचडी, 'पारिवारिक संसाधन प्रबन्ध एवं उपभोक्ता विज्ञान विभाग, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

पालक का वैज्ञानिक नाम स्पिनासिया ओलेरेसिया है। हरी पालक मे भरपूर मात्रा मे लगभग सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं , जो हमारे शरीर को बहुत ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसे लगभग हर कोई बड़े चाव से खाना पसंद करता है। सर्दी के मौसम में कई तरह के साग मिलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग पालक का साग खाना पसंद करते हैं। पालक, में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पालक मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। **सेवॉय पालक:** सेवॉय पालक गाढ़े हरे रंग के होते हैं और इसके पत्ते सिकुड़े हुए होते हैं, ये खाने मे बहुत स्वादिष्ट होता है, इसमें पोषक तत्वों भरपूर मात्रा में मिलता है।

सेमी-सेवॉय पालक: सेमी-सेवॉय पालक सेवॉय पालक के तुलना मे कम सिकुड़े हुए होते हैं। इसे घर मे भी उगाया जा सकता है। इसमे भी भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। **स्मूथ-लीफ पालक:** स्मूथ-लीफ पालक की पत्तियां सेवॉय पालक और सेमी-सेवॉय पालक की तुलना मे ज्यादा चौड़ा और मुलायम होता है। इसमे भी भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं।

पालक में मौजूद पोषक तत्व प्रति 100 ग्राम.

विटामिन, कैलोरी: 23, प्रोटीन: 2.9 ग्राम, कार्ब्स: 3.6 ग्राम, चीनी: 0.4 ग्राम, फाइबर: 2.2 ग्राम, फैट: 0.4 ग्राम, कैल्शियम: 30 मिलीग्राम, आयरन: 0.81 ग्राम, मैग्नीशियम: 24 मिलीग्राम, पोटेशियम:167 मिलीग्राम

पालक के सेवन से होने वाले सेहत लाभ: पालक के नियमित सेवन से वजन कम होता है। पालक के फाइबर पाचनशक्ति को बढ़ाते हैं। पालक में क्लोरोफिल और सेहत दुरुस्त रखने वाले कैरोटेनॉएड्स जैसे बीटा-कैरोटीन होते हैं, जिनमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-कैंसर तत्व होते हैं। लौह तत्व शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है। इससे शरीर के रक्त में स्थित रक्ताणुओं में रोग निरोधक क्षमता तथा रक्त में रक्तिमा आती है। पालक शरीर में रक्त की कमी नहीं होने देता है। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के कारण कई गंभीर बीमारियां हो रही हैं। इससे किडनी और दिल संबंधी रोग व स्ट्रोक बढ़ता है। साथ ही, इसमें तनाव को दूर करने वाले तत्व भी मौजूद होते हैं, जो हाइपरटेंशन कम करता है। इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। इसके सेवन से महिलाएं एनीमिया से बच सकती हैं। पालक में प्रचुर मात्रा मे मौजूद मैग्नीशियम, विटामिन्स व रेशा जैसे पोषक तत्व होते है, जो कैंसर के किटाणुओं को हमारे शरीर में आने से रोकता है, जिससे हमे कैंसर होने का संभावना कुछ हद तक कम कर देता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। पालक मस्तिष्क स्वास्थ्य और तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पालक के नियमित सेवन से गठिया नामक रोग को दूर किया जा सकता है।

अवसर प्रदान करने के लिए हर जिले में आत्मा परियोजना संचालित की जा रही

प्राकृतिक खेती बनी फायदे का सौदा

भोपाल। जागत गांव हमार

परम्परागत खेती अब बीते दौर की बात हो गई है। नया दौर उन्नत तकनीक और प्राकृतिक खेती का है। बालाघाट जिले के किसानों ने इस व्यवहारिक तथ्य को समझा और प्राकृतिक तरीके से खेती कर सर्वोत्तम किसान का सम्मान हासिल किया। किसानों की प्रगतिशीलता और उद्यमशीलता को अवसर प्रदान करने के लिए हर जिले में आत्मा परियोजना संचालित की जा रही है। इस परियोजना में बालाघाट जिले में अत्यंत सराहनीय काम हुआ है। प्राकृतिक खेती अपनाकर यहां के पांच किसानों ने न केवल मुनाफा कमाया, बल्कि सर्वोत्तम किसान होने का सम्मान भी हासिल किया है।

इन्हें प्राकृतिक खेती के प्रसार उन्नत कृषि तकनीकों का इस्तेमाल करने एवं पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। बालाघाट जिले के कटंगी के किसान रामेश्वर चौरीकर ने प्राकृतिक रूप से मशरूम की खेती करने के लिये रोचक तरीका अपनाया। इसके लिए रामेश्वर ने 10 गुणा 10 के कमरे में दीवारों पर टाट और सतह पर रेत का उपयोग किया और सुबह-शाम स्प्रे कर इस कक्ष को वातानुकूलित बना लिया है। क्योंकि मशरूम की खेती के लिए तापमान 16 से 25 डिग्री सेल्सियस तक जरूरत के मुताबिक मेन्टेन करके रखना पड़ता है। 45 से 90 दिन में इसकी फसल आती है। मशरूम बाजार में 200 से 250 रूपये किलो तक बिकता है। पहली फसल बेचने पर ही रामेश्वर को अच्छा खासा मुनाफा हुआ। मशरूम की खेती के इस नवाचारी तरीके के लिये रामेश्वर को जिले का सर्वोत्तम किसान पुरस्कार-मिला है। इसी तरह आगरवाडा (कटंगी) के दीनदयाल को उन्नत कृषि तकनीकों से खेती- किसानी के लिए, थानेगांव (वारासिवनी) के नरेन्द्र सुलकिया को कृषि उद्यानिकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये, बटरमारा (किरनापुर) के हिरेन्द्र गुरवे को रेशम कीट पालन के लिये और चिचरंगपुर (बिरसा) के जंगल सिंह को उन्नत नस्लों के पशुपालन से अतिरिक्त आय अर्जन के लिए जिलास्तरीय सर्वोत्तम किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

28 किसानों को मिला ब्लॉक स्तरीय सर्वोत्तम पुरस्कार

इसके अलावा अन्य 28 प्रगतिशील किसानों को उन्नत कृषि की विभिन्न श्रेणियों में ब्लॉकस्तरीय सर्वोत्तम किसान पुरस्कार दिया गया है। जिले के पांच सर्वोत्तम स्व-सहायता समूहों को कृषि में विशेष प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। बालाघाट जिले में प्राकृतिक (आर्गेनिक) खेती-किसानी यहां के किसानों के लिए बड़े फायदे का सौदा बन गई है। जिले के बडगांव स्थित किसान विकास केन्द्र में किसानों को उन्नत व प्रगतिशील खेती के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट कराए जाते हैं। इन्हीं प्रशिक्षणों एवं एक्सपोजर विजिट्स में मिले नवाचारों से प्रेरित होकर किसानों ने यहां के किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। प्राकृतिक खेती पर्यावरण संरक्षण में भी सहयोगी है। इससे किसानों के एक पंथ दो काज पूरे हो रहे हैं।

तीन किलोवॉट के सौर संयन्त्र लगाने पर 78 हजार सब्सिडी

पीएम सूर्य घर योजना में मिलेगी एक करोड़ घरों को मुफ्त की बिजली

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार द्वारा देश के एक करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएम सूर्य घर योजना प्रारंभ की गई है। लोगों को इस योजना का लाभ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने देना शुरू कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत एक किलोवॉट सोलर संयन्त्र लगाने पर 30 हजार रूपये, दो किलोवॉट सोलर संयन्त्र लगाने पर 60 हजार रुपए तथा तीन किलोवॉट या उससे ऊपर के सोलर संयन्त्र स्थापना पर 78 हजार रुपए की सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही है। यह सब्सिडी पहले से ज्यादा है। इसके लिए देशभर के एक करोड़ उपभोक्ताओं को पीएम सूर्य घर योजना से जोड़ने का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने जा रही है। इस नई योजना में अब एक किलोवॉट पर 30 हजार, दो किलोवॉट पर 60 हजार एवं तीन किलोवॉट या उससे अधिक के सोलर प्लांट पर 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी।

60 हजार रुपए सब्सिडी

गौरतलब है कि दिसंबर-2023 की स्थिति में केन्द्र द्वारा प्रति किलोवॉट 14 हजार 588 रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी जो कि जनवरी-24 में बढ़ाकर 18 हजार प्रति किलोवॉट कर दी गई थी। जिसे अब और बढ़ाकर दो किलोवॉट तक 30 हजार प्रति किलोवॉट कर दी गई है। इस तरह दिसंबर की तुलना में 13 फरवरी 2024 के बाद लगने वाले दो किलोवॉट तक के सौर्य संयन्त्र पर मिलने वाली सब्सिडी 36 हजार के स्थान पर अब उपभोक्ता को 60 हजार रुपए की सब्सिडी मिलेगी।

आर्थिक बचत पर फोकस

पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली की सुलभता के साथ आर्थिक बचत करवाना शामिल है। मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का लाभ देकर लोगों को प्रोत्साहित करना है। पीएम सूर्य घर योजना से जुड़ने पर पर्यावरण के हितों की रक्षा हो सकेगी। योजना में अधिक से अधिक लोग जुड़कर लाभ ले सकते हैं।

मत्स्य महासंघ समिति की बैठक में मंत्री ने कहा

प्रदेश में मछुआ कल्याण की योजनाओं को बढ़ाया जाएगा

भोपाल। जागत गांव हमार

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नारायण सिंह पवार की अध्यक्षता में मत्स्य महासंघ की कामकाज समिति की 109वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वर्ष 2024-25 के बजट का अनुमोदन किया गया। मंत्री ने महासंघ कामकाज इंदिरा सागर एवं बरगी इकाईयों की समीक्षा करते हुए कहा कि महासंघ के जलाशयों की उत्पादन क्षमता को 50 किलो प्रति हेक्टेयर लाया जाए। वर्तमान में जलाशयों का औसत उत्पादन 35 किलो प्रति हेक्टेयर है। इसे बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। महासंघ की वर्तमान आय में यथोचित वृद्धि सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मछुआ कल्याण की योजनाओं एवं विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा।

अधिक सफलता प्राप्त होगी

मंत्री ने कहा कि भदभदा परिक्षेत्र में एक उपयुक्त विश्राम गृह का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महासंघ द्वारा शासन को दी जाने वाली छह रुपए किलो की रायल्टी को भी बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करे। इंदिरा सागर जलाशय जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय है उसकी निविदा यथा शीघ्र आमंत्रित कर सक्षम निविदाकारों से संपर्क कर उन्हें प्रेरित करे, इससे अधिक सफलता प्राप्त होगी।

लक्ष्यों को तत्परता से पूर्ण करें

महासंघ के अन्य जलाशयों जिनकी निविदा नहीं हुई है, उनकी निविदा शीघ्र आमंत्रित करने के भी निर्देश दिए। इससे मछली उत्पादन में वृद्धि हो। बैठक में अंकेक्षण आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा कर अनुमोदन किया गया। मत्स्य उत्पादन के लक्ष्यों को तत्परता से पूर्ण करें। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाए। नियमानुसार प्रगति की जानकारी प्राप्त कर उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जाएं।

नालों के गंदे पानी को फिल्टर करने बडौदा में बनेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

स्वच्छत भारत मिशन के तहत मिली राज्य शासन से मंजूरी

अब प्रदूषित नहीं होगी अहेली नदी, क्योंकि फिल्टर होने के बाद पहुंचेगा नालों का पानी

श्योपुर। जागत गांव हमार

बड़ौदा कस्बे के दोनों नालों का गंदा पानी अब अहेली नदी के जल को प्रदूषित नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए बडौदा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इस प्लांट के माध्यम से बडौदा कस्बे के अंदर से आने वाले दोनों नालों का गंदा फिल्टर किया जाएगा।

नालों का पानी फिल्टर किए जाने के बाद ही अहेली नदी में जाएगा। जिससे अहेली नदी प्रदूषित होने से बची रहेगी। बड़ौदा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) 2.0 के अंतर्गत मिली है। इस पर लगभग 4 करोड 40 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। शासन से मंजूरी मिलने के बाद नगर परिषद बड़ौदा ने इस ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराए जाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल, बड़ौदा कस्बे के अंदर से होकर दो नाले गुजरते है। इनमें प्रताप स्कूल वाला नाला और अस्पताल रोड होते हुए निकलने वाला शामिल है। इन दोनो नालों में पूरे बडौदा कस्बे के घरों का गंदा पानी गिरता है। यह दोनों नाले नगर परिषद कार्यालय के पीछे मिल जाते है और फिर यहां से एक नाले में सारा गंदा पानी एकत्रित होकर अहेली नदी में पहुंचता है जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए नगर परिषद बड़ौदा ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराए जाने संबंधी एक प्रस्ताव स्वच्छ भारत मिशन के तहत तैयार करके शासन की ओर से भेजा गया।

4 करोड 40 लाख से बनेगा ट्रीटमेंट प्लांट

बताया गया है कि शासन के द्वारा बड़ौदा नगर परिषद के प्रस्ताव पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्वीकृत करते हुए 4 करोड 39 लाख 99 हजार रूपए की राशि स्वीकृत कर दी है। स्वीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के मुताबिक पहले बड़ौदा कस्बे के दोनों नालों की स्थिति को सुधारते हुए उन्हें एक दूसरे से जोडा जाएगा और फिर नगर परिषद कार्यालय के पीछे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए नालों के गंदे पानी की सफाई की जाएगी। इसके बाद पानी को अहेली नदी में छोडा जाएगा। जिसे नाले के जरिए ये पानी अहेली नदी तक पहुंचेगा,उस नाले की स्थिति भी सुधारी जाएगी।

अहेली नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
भरोसी बाई सुमन, अध्यक्ष नप बड़ौदा

12 महीने में कंपलीट करना होगा काम

बड़ौदा में स्वीकृत किए गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए शासन ने नगर परिषद बड़ौदा को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया है। इसके बाद बड़ौदा नगर परिषद के द्वारा इस संबंध में टेंडर जारी कर दिए गए है। बताया गया है कि जो कंपनी इस प्लांट का निर्माण करना चाहेगी, वह इसके लिए टेंडर डालेगी। इसके बाद कंपनी का निर्धारण किया जाएगा। बताया गया है कि जो भी कंपनी इस प्लांट को लगाने का काम अपने हाथ में लेगी,उसे इस काम को 12 महीने में कंपलीट करना होगा। क्योंकि इस काम को कंपलीट करने की समयावधि शासन के द्वारा 12 महीने निर्धारित की गई है।

चंबल-पार्वती-कालीसिंध लिंक परियोजना के तहत तैयार किया गया प्रस्ताव

श्यामपुर के पास बनेगा बैराज, 60 गांवों के किसानों को मिलेगा पानी

श्योपुर। जागत गांव हमार

चंबल पार्वती कालीसिंध लिंक परियोजना से जिले में सिंचाई का रकवा बढने वाला है। क्योंकि इस परियोजना के तहत श्योपुर जिले में श्यामपुर के नजदीक कूनो नदी पर एक बडा बैराज बनाया जाएगा। जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। इस बैराज से 60 गांवों की 20 हजार हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा। इसमें विजयपुर-वीरपुर क्षेत्र के 45 गांव और मुरैना जिले के लिए सबलगढ़ क्षेत्र के 15 गांव शामिल है। बताया जा रहा है कि इस बड़े बांध की डीपीआर बनाकर विभाग ने शासन को मंजूरी के लिए भेज दी है।

विजयपुर-वीरपुर क्षेत्र के ये गांव होंगे लाभांवित- श्यामपुर के पास कूनो नदी पर जो बैराज बनाया जाएगा,उसके माध्यम से विजयपुर और वीरपुर क्षेत्र के जिन गांवों को लाभ होगा, उनमें उमरी खुर्द, अगरा, शाहपुर खुर्द, चेंटीखेड़ा, रणसिंह पुरा, देहरी, डोंडईकला, घोरदे, झारबड़ौदा, अरोंद, मढ़ा, खितरपाल, दूल्हावाला, किशनपुरा, अहीरी, लोसघानी, पार्वती बड़ौदा, पिपरवास, रनावद, इटवई,बांगरोद, बरखेड़ा, लाडपुरा, बेनीपुरा, भारखोह, भैंसाई, गोहरा, लक्ष्मणपुरा, अंधूपुरा, सुनवई,

विजयपुर, खुर्दबरा, दोर्द, गुर्जा, बरदुला, बराकलां, चंदेली, मेवरा, बिचपुरी, गोपालपुरा, काठोन, गोबर आदि गांव शामिल हैं। जबकि अन्य गांव मुरैना जिले के शामिल हैं।

कपीला गांव के पास भी बनेगा बांध

लगभग 6600 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित कूनो कॉम्प्लेक्स परियोजना में भी श्यामपुर बैराज शामिल है। इस परियोजना में कूनो और इसकी सहायक नदियों पर कुल 6 बांध बनने हैं। बताया जा रहा है कि कूनो कॉम्प्लेक्स परियोजना भी अब चंबल-पार्वती-कालीसिंध लिंक परियोजना में शामिल होगी, क्योंकि कूनो नदी को भी इस परियोजना में जोड़ा जा रहा है। इसके तहत कराहल तहसील क्षेत्र में कपीला गांव के पास कूनो नदी पर बांध बनाया जाएगा। जिसके जरिए शिवपुरी और गुना जिले के गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा।

कूनो कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत प्रस्तावित श्यामपुर बैराज और कटीला बांध के लिए डीपीआर बनाकर शासन को भेजी हुई। वहां से स्वीकृत होने के बाद इन बांधों का निर्माण शुरू होगा।
विनोद शर्मा, कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग शिवपुरी

2018 में घोषणा हुई, किसानों के विरोध के बाद 30 मार्च 2023 को पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नए सर्वे के आदेश दिए थे, वो अब तक नहीं हुए

दो लोस चुनाव निपट गए फिर भी पटरी पर नहीं आई सरकार की एक्सप्रेस-वे

श्योपुर । जागत गांव हमार

चंबल संभाग के तीन जिले मुरैना, भिंड और श्योपुर से एक्सप्रेस-वे गुजारकर अंचल को राजस्थान व उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए छह साल पहले एक्सप्रेस-वे की घोषणा हुई। छह साल में पांच बार इस एक्सप्रेस-वे का नाम बदला गया और तीन बार अलाइनमेंट में बदलाव किया गया, लेकिन यह एक्सप्रेस-वे धरातल पर नहीं आया। अब एक साल से पूरी परियोजना ठंडे बस्ते में पड़ी है। 2018 के विधानसभा, 2019 के लोकसभा और 2020 के विधानसभा उपचुनाव में इसे मुद्दा बनाकर सत्ताधारी दल ने खूब वोट मांगे, पर पिछले विधानसभा और अब लोकसभा से पहले एक्सप्रेस-वे का नाम लेने से भी नेता कतरा रहे हैं।

गौरतलब है, कि 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले मप्र सरकार ने चंबल संभाग के तीनों जिलों श्योपुर, मुरैना व भिंड से मेगा हाईवे निकालने के लिए एक्सप्रेस-वे की घोषणा की। इसका पहला नाम एक्सप्रेस-वे रखा गया, जिसे बदलकर चंबल एक्सप्रेस-वे किया गया, तीसरी बार नाम बदलकर चंबल प्रोग्रेस-वे किया गया। बाद में इस मेगा हाईवे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखते हुए चंबल शब्द हटाकर अटल प्रोग्रेस-वे कर दिया गया। साल 2022 में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस एक्सप्रेस-वे को भारत माला परियोजना में शामिल करते हुए इसका नाम अटल प्रगति पथ कर दिया गया। जब यह परियोजना का ऐलान हुआ, तब इसकी लागत का अनुमान 3500 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गया, जो लगातार बढ़ते-बढ़ते 8000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, पर निर्माण के नाम पर एक ईंट नहीं रोपी गई।

तीन बार बदला अलाइनमेंट

सबसे पहले यह एक्सप्रेस-वे चंबल नदी किनारे बीहड़ों से होकर बनना था, इसके लिए एनएचएआइ ने बीहड़ों में सर्वे कर अलाइनमेंट भी बना लिया। पहली बार इसका मार्ग तब बदला गया, जब राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंक्चुरी की जद में आने के कारण इसके निर्माण को एनओसी नहीं मिली। इसीलिए एक्सप्रेस-वे को घड़ियाल सेंक्चुरी की जद से बाहर बीहड़ों में बनाने का सर्वे हुआ और अलाइनमेंट भी बना। लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बीहड़ों में एक्सप्रेस-वे के निर्माण को पर्यावरण व चंबल नदी के जलीयजीवों के लिए खतरनाक बताते हुए, बीहड़ों में निर्माण पर रोक लगा दी। इसके बाद तीसरी बार फिर सर्वे हुआ और सरकारी से ज्यादा निजी क्षेत्र की जमीन का चिन्हित कर अधिग्रहण तक शुरू हो गया, लेकिन मुरैना, भिंड और श्योपुर के किसानों ने भारी विरोध किया, क्योंकि 96 गांवों के 4300 किसान भूमिहीन हो रहे थे। इस विरोध के कारण 30 मार्च 2023 को तात्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीसरी बार के सर्वे को निरस्त करते हुए यह आदेश दिया, कि नया सर्वे कर पुन: ऐसा अलाइनमेंट बनाया जाए, जिसमें सरकारी जमीन का उपयोग अधिक हो। पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एनएचएआइ ने अटल प्रगति पथ की पूरी प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल रखा है।

पहले 360 किमी का था, जो बढ़कर हुआ 404 किमी का

जब अटल प्रोग्रेस-वे बीहड़ों से होकर बनने वाला था, तब मुरैना, श्योपुर व भिंड जिले में इसकी कुल लंबाई 360 किलोमीटर थी। दूसरे अलाइनमेंट में अटल प्रोग्रेस-वे को उप्र में बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस से जोड़ने की योजना थी, इस कारण लंबाई 44 किलोमीटर बढ़कर 404 किमी हो गई। अब तीसरे सर्वे में यह लंबाई कम होगी या बढ़ेगी, इस पर भी कयास लग रहे हैं। सरकारी जमीन का उपयोग होने से सरकार की लागत जरूर कम हो जाएगी। क्योंकि सरकार को भूमि अधिग्रहण पर होने वाला तीन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च नहीं करना पड़ेगा।

अटल प्रगति पथ के नए सर्वे के लिए मार्च 2023 के बाद एनएचएआइ से कोई आदेश फिलहाल नहीं आए हैं। यह मामला एनएचएआइ के मुख्यालय में विचाराधीन है, वहां से हमें जो दिशा निर्देश मिलेंगे उस पर काम शुरू कर देंगे, फिलहाल तो कुछ भी नहीं है।

अवनीत सिद्धार्थ
परियोजना प्रबंधक, एनएचएआइ

केवीके द्वारा किसानों के खेतों पर ड्रोन का प्रदर्शन कराया गया

किसानों को खेतों में ड्रोन द्वारा नैनो यूरिया का छिड़काव करके दिखाया गया

लहार (भिंड) । जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र, लहार जिले के किसानों को हर उन्नत तकनीकी पहुंचाने के साथ ही कृषि में नवीनतम कृषि यंत्रों को भी पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में आज कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा लहार क्षेत्र के गिरवासा गांव में निकरा परियोजना अंतर्गत किसानों के खेतों पर ड्रोन का प्रदर्शन आयोजित किया गया। ड्रोन के माध्यम से गेहूं की फसल पर नैनो यूरिया का छिड़काव करके किसानों को दिखाया गया। इस अवसर पर गांव के किसानों ने एकत्रित होकर ड्रोन के माध्यम से छिड़काव के तरीके को देखा एवं सराया गया।

कृषि में ड्रोन की अनुमति मिलने के बाद अब धीरे-धीरे इसकी पहुंच आम किसानों तक होने लगी है। ड्रोन के माध्यम से फसलों पर कीटनाशकों एवं उर्वरकों के छिड़काव के तरीके को दिखाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र लहार द्वारा अभिनव पहल करते हुए गिरवासा गांव में निकरा परियोजना अंतर्गत ड्रोन से नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन के तहत कुछ किसानों की गेहूं की फसल पर नैनो यूरिया का छिड़काव करके किसानों को दिखाया गया। इस अवसर पर केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एसपी सिंह ने बताया की एक एकड़ फसल पर हाथ से स्प्रे करने में दो से तीन मजदूरों को कम से कम एक दिन का समय लगता है। वहीं ड्रोन के माध्यम से एक एकड़ भूमि मात्र 15 मिनट में उर्वरक अथवा कीटनाशक का छिड़काव आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करने पर समय, श्रम एवं धन तीनों की ही बचत होती है। कृषि में ड्रोन का प्रयोग भारत सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है। खेती में आने वाले समय में ड्रोन का प्रयोग निश्चित रूप से बढ़ेगा। डॉ. सिंह बताया कि भारत सरकार ड्रोन दीदी के माध्यम से महिलाओ और युवतियों को स्वावलंबन के साथ ही ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग आदि योजना को संचालित कर रही है। भारत सरकार यह कार्य नाबार्ड के माध्यम से संचालित हो रहा है।

केवीके द्वारा प्रदर्शन हेतु ड्रोन राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के सीएआईई केंद्र से मगाया गया था। जिसको सीएआईई केंद्र, ग्वालियर के ड्रोन पायलट मनीष आर्य एवं अवध बिहारी पाल द्वारा संचालित किया गया था। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. आरपीएस तोमर एवं निकरा परियोजना के एसआरएफ दीपेंद्र शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

बढ़ेगी हादसों की आशंका, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान

जैदा मंडी रोड की हालत जर्जर, फसल बेचने मंडी जाने वाले किसानों को उठानी पड़ेगी परेशानी

श्योपुर । जागत गांव हमार

जैदा मंडी रोड का निर्माण कार्य कराने के लिए छह साल पहले मंडी बोर्ड भोपाल से मंजूरी मिली थी। लेकिन आज भी यह सड़क अधूरी पड़ी है। वहीं बताया जा रहा है कि अ रबी फसल को बेचने के लिए किसानों के वाहनों की आवाजाही बढ़ेगी। ऐसे में सड़क पर हुए गड्ढे किसानों के लिए हादसों सबब बनेंगे। आगामी दिनों में अब इस मार्ग पर किसानों के वाहनों की आवाजाही बढ़ेगी। क्योंकि किसान अपनी रबी फसलों को बेचने के लिए मंडी में खुली नीलामी के साथ ही मंडी में बनाए जाने वाले गेहूं, चना व सरसों के समर्थन मूल्य के खरीद केंद्रों पर उपज लेकर आएंगे। ऐसे में सड़क के ये दर्जनों गड्ढे किसानों के लिए हादसों का सबब बनेंगे। बावजूद इसके न तो मंडी बोर्ड के अफसर और इंजीनियर ध्यान दे रहे हैं और न ही जिला प्रशासन के अफसर।

सड़क निर्माण पर खर्च हो गए तीन करोड़ रुपए

मंडी बोर्ड भोपाल ने छह साल पहले जैदा मंडी लिंक रोड को निर्माण को मंजूरी दी। लगभग तीन करोड़ से स्वीकृत हुए लगभग तीन किलोमीटर (मंडी के कोटा रोड वाले गेट के सामने के रोड सहित) के इस रोड का निर्माण श्योपुर-कोटा मार्ग से मंडी गेट के सामने होकर चंबल नहर तक होना था। हालांकि संबंधित निर्माण ठेकेदार ने काम भी शुरू किया, लेकिन काम शुरू से ही गुणवत्ताहीन रहा, लिहाजा इधर सड़क बनी और उधर से उखड़ती नजर आई। विशेष बात यह है कि सड़क पर डामर की एक ओर सीलकोट होनी थी, लेकिन अब बीते 4 साल से काम बंद है और सड़क अधूरी पड़ी है।

रिवाइज में मंजूर हुए एक करोड़

विभागीय अधिकारियों के अनुसार सड़क में डामर की एक सीलकोट होनी है, जिसके लिए लागत बढ़ने के बाद रिवाइज एस्टीमेट बनाकर भेजा गया। विधानसभा चुनाव से पहले लगभग एक करोड़ रुपए की लागत से रिवाइज एस्टीमेट को मंजूरी भी मिल गई है। लेकिन अब मंडी बोर्ड के अधिकारी और इंजीनियर इस सड़क का काम पूरा नहीं करा पा रहे हैं। जिससे सड़क पूरी तरह बदहाल है।

रिवाइज एस्टीमेट स्वीकृत हो चुका है और हमने ठेकेदार को नोटिस भी दिया है। लेकिन ठेकेदार का कहना है कि 4 साल पहले की रेट से अब लागत बढ़ गई है, लिहाजा उस पर ब्याज दिया जाए। इस संबंध में हमने बोर्ड को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा है।

बृजेश जैन, कार्यपालन यंत्री, मंडी बोर्ड मुरैना

दुनिया में मक्का उत्पादन में भारत का 7वां नंबर

मक्का की खेती फायदे का सौदा बनते हुए दिख रही

भोपाल। जागत गांव हमार

क्रिकेट में छक्के की कीमत सबसे ज्यादा होती है। मसलन, जो भी बल्लेबाज क्रिकेट पिच पर धुंआधार बैटिंग करते हुए छक्के की बरसात करने का हुनर रखता है, वह क्रिकेट प्रेमियों के दिल में आसानी से जगह बन लेता है। बात खेती यानी किसानी पिच की जाए तो नकदी फसलों किसानों को अधिक प्रभावित करती हैं, लेकिन बीते कुछ सालों से मक्के की खेती किसानों को प्रभावित कर रही है। मसलन, खेती की पिच पर मक्का ब्राउंडी बाहर छक्का लगाने की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मक्का किसानों के लिए पीला सोना बन सकता है। मक्के की खेती किसानों के लिए कितनी फायदेमंद है।

पहले मक्के का गुणा-गणित- भारत में मक्के की खेती पारंपरिक तौर पर होती है। मक्का भारत की पुरातन फसल है। पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग वाला स्वैग इसका एक बड़ा उदाहरण है। मक्के की खेती के गुणा-गणित की बात करें तो दुनिया के देशों में मक्का उत्पादन में भारत का नंबर 7वां है, जिसकी कुल विश्व उत्पादन में हिस्सेदारी 2 फीसदी है। अगर बात करें तो मौजूदा समय में भारत का प्रति वर्ष मक्का उत्पादन 30 एमटी से अधिक है।

तेजी से बढ़ रही मक्का की मांग

मक्के की मांग देश-दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। बीते कुछ दशकों तक मक्का खाद्यान्न का मुख्य हिस्सा था, लेकिन गेहूं-चावल के आहार संस्कृति का हिस्सा बनने के बाद आम आदमी की थाली से मक्के की दूरी बढ़ती गई, लेकिन बीते कुछ सालों में आम आदमी की खुराक में सुधार के साथ ही मक्के की मांग में तेजी आई है, जिसमें प्रमुख तौर पर सबसे अधिक मक्के की मांग पोल्ट्री सेक्टर में बनी हुई है। इसके साथ ही पशुचारा, स्टार्च, एक्सपोर्ट और प्रोसेस्ड फूड में मक्के की मांग ने नए मुकाम पाएं हैं।

इथेनॉल क्रांति बनाएगा मक्के को सोना

मौजूदा वक्त में मक्का किसानों के लिए पीला सोना बनने की कोशिश करता हुए दिख रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि इथेनॉल क्रांति मक्के को पीला सोना बनाने की गांरटी है। असल में देश के अंदर इथेनॉल को पेट्रोल-डीजल का विकल्प माना जा रहा है। इसको लेकर सरकार काम भी कर रही है। इसी कड़ी में पेट्रोल में इथेनॉल की समिश्रण किया जा रहा है। जिसके तहत मौजूदा वक्त में 20 फीसदी इथेनॉल का समिश्रण पेट्रोल में करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, जबकि 80 फीसदी समिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं कई फसलों से इथेनॉल बनाए जाने की योजना है, जिसके तहत मौजूदा वक्त में गन्ने, टूटे चावल से इथेनॉल बनाया जा रहा है। ऐसे में मक्के से बढ़े स्तर पर इथेनॉल बनाने की योजना प्रस्तावित है, जो मक्के के भाग्य बदल सकता है।

छह फीसदी मक्का एक्सपोर्ट

मक्के की मांग की इस हिस्सेदारी को लेकर भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान की एक रिपोर्ट कहती है कि मौजूदा समय में कुल उत्पादित मक्के में से 47 फीसदी मक्का पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होता है, जबकि 14 फीसदी स्टार्च, 13-13 फीसदी मानव और पशुआहार यानी भोजन और पशुचारा में प्रयोग होता है, जबकि 7 फीसदी मक्का प्रोसेस्ड फूड और 6 फीसदी मक्का एक्सपोर्ट के तौर पर प्रयोग होता है।

मक्के की एमएसपी

बेशक, मक्के से अभी इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया शुरुआती चरण पर है, लेकिन बाकी अन्य सेक्टरों में मक्के की भरपूर मांग बनी हुई है। मसलन, मौजूदा वक्त में बाजार के अंदर मक्के के दाम एमएसपी से अधिक चल रहे हैं। सरकार ने मक्के की एमएसपी 2090 रुपए क्विंटल निर्धारित की हुई है, इसके इतर देश के कई बाजारों में एमएसपी के दाम 2200 से 2300 रुपए क्विंटल तक चल रहे हैं।

मक्के पर नजर

खेती की पिच पर मक्के के अंदर शानदार छक्का मारने की काबिलियत को नीति निर्माता समझ गए हैं, जिसके बाद से मक्के की खेती का दायरा बढ़ाने के प्रयास भी केंद्र सरकार की तरफ से शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार एमएसपी गारंटी पर मक्के की खरीद की योजना केंद्र सरकार बना रही है। बीते दिनों आंदोलनकारी किसानों को केंद्र सरकार ने 5 फसलों को 5 साल खरीदने की गारंटी दी थी, जिसमें मक्का भी शामिल था। ऐसे में मक्के की महिमा को समझा जा सकता है।

समाचार पत्र के स्वामित्व एवं अन्य विषयों से संबंधित विवरण
घोषणा
फार्म-4

1. प्रकाशन स्थल	भोपाल
2. प्रकाशन अवधि	साप्ताहिक
3.मुद्रक का नाम	अजय कुमार द्विवेदी
क्या भारत का नागरिक है	हां
पता	एमआईजी- 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास, जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश
4. प्रकाशक का नाम	अजय कुमार द्विवेदी
क्या भारत का नागरिक है	हां
पता	एमआईजी- 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास, जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश
5. संपादक का नाम	अजय कुमार द्विवेदी
क्या भारत का नागरिक है	हां
पता	एमआईजी- 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास, जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों	नहीं

मैं अजय कुमार द्विवेदी एतदद्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए सभी विवरण सत्य हैं

हस्ताक्षर
अजय कुमार द्विवेदी
(प्रकाशक के हस्ताक्षर)

बांस से कलात्मक वस्तु सृजन का केंद्र बनेगा शुजालपुर

निर्माण कार्यो के भूमिपूजन के दौरन उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा

भोपाल। विश्व मंच पर देश की शान को पुनर्स्थापित करने के लिए हमें अपने लोगों की उपलब्धियों पर गर्व करने की परंपरा विकसित करनी होगी। भारतीय ज्ञान परम्परा में निहित वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पुनर्शोध की जरूरत है। स्वत्तव के भाव के उद्घोष के साथ ही स्वाभिमानी राष्ट्र 2047 के विकसित भारत का संकल्प साकार होगा। इसके लिए हमें अपने परंपरागत ज्ञान को आधुनिक तकनीक समावेशी बनाकर अपनी विशिष्टता को विश्व पटल पर रखना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसरण में शिक्षा में परिवर्तन कर कौशलपरक एवं रोजगारमूलक शिक्षा पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह बात उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार ने स्वातंत्र्य वीर सावरकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रांगण शुजालपुर में कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्र के लोकार्पण के दौरान कही। यह केंद्र लागत राशि 1 करोड़ 7 लाख 11 हजार रुपए राशि से निर्मित स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत मप्र राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड का महत्वाकांक्षी उपक्रम है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते है कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

“आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा”

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)